

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्गा/09/2013-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 33 ]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 18 अगस्त 2023—श्रावण 27, शक 1945

### विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

## भाग १

### राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 जून 2023

क्रमांक ई 1-01/2023/एक-2.—राज्य शासन एतद्वारा सुश्री श्रुति सिंह, भा.प्र.से. (2006) को अंतः संवर्गीय प्रतिनियुक्ति से लौटने पर अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यन्त सचिव, मंत्रालय के पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

## कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 जून 2023

क्रमांक एफ 1-23/2022/कौ.वि./42.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्राचार्य वर्ग-2 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 में नियुक्त करते हुए अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई संस्था में पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र. (1)	अभ्यर्थी का नाम एवं पता (2)	प्रवर्ग (3)	चयन का वर्ग (4)	पदस्थापना स्थल (5)
1.	श्री छत्रपाल, पिता श्री नेतराम, मकान नंबर 257, कैलाश चौक, शारदा पारा, कैम्प-2, भिलाई, थाना-छावनी, जिला-दुर्ग, पिन-490001.	अ.पि.वर्ग	UR_PH_NC AT_OL	आई.टी.आई., रामानुजगंज, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज.
2.	श्री महेन्द्र सोनी, पिता श्री हुलाश चन्द्र सोनी, एच नंबर 46, वार्ड नंबर 01, दर्री रोड कोरबा, जिला-कोरबा. पिन-495678.	अ.पि.वर्ग	UR_PH_ OA	आई.टी.आई., मानपुर, जिला-मानपुर-मोहला-अंबागढ़ चौकी.
3.	श्री कन्हैया लाल सोनी, पिता श्री मनहरण लाल सोनी, ग्राम-बंधी, पोस्ट-बचरवार, तहसील-पेण्ड्रा, जिला-गौरेला-पेण्ड्रा- मरवाही.	अ.पि.वर्ग	UR_PH_NC AT_OL	आई.टी.आई., डौंडी, जिला-बालोद.

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :—

(1) उपरोक्तानुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टापपेण्ड देय होगा :—

प्रथम वर्ष — पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत.  
द्वितीय वर्ष — पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत.  
तृतीय वर्ष — पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत.

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टापपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे.

(2) अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के योग्य पाये जाने की प्रत्याशा में नियुक्त किया जा रहा है. मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त हो जायेगा. मेडिकल बोर्ड का स्वस्थता प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.

(3) शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत होने की स्थिति में अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा.

(4) कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण में जमा करना होगा.

- (5) अभ्यर्थी को स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट) मूल रूप से प्रस्तुत करेगा। जिसकी सत्यापित छायाप्रति संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण के कार्यालय में रहेगी।
- (6) परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी।
- (7) अभ्यर्थी के परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं विभागीय सेवा भर्ती नियम के अंतर्गत शासित होगी।
- (8) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा। आदेश में टंकण त्रुटि होने पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी ही मान्य की जावेगी।
- (9) अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये, तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक् किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी।
- (10) चयनित प्रत्याशियों को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- (11) उपर्युक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 21 जून 2023

क्रमांक एफ 1-23/2022/कौ.वि./42.—छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्राचार्य वर्ग-2 के पद पर वेतन मैट्रिक्स लेवल-12 में प्रावधिक (Provisional) रूप से नियुक्त करते हुए अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई संस्था में पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र. (1)	अभ्यर्थी का नाम एवं पता (2)	प्रवर्ग (3)	चयन का वर्ग (4)	पदस्थापना स्थल (5)
1.	श्री जयप्रकाश पटेल, पिता श्री हृषिकेश पटेल, मकान नंबर 70/ड, ग्राम-बनहर, पोस्ट-गोडा, तहसील-सारंगढ़, जिला-सारंगढ़-बिलाईगढ़. पिन-496445	अ.पि.वर्ग	UR_PH_OL	आई.टी.आई., देवभोग, जिला-गरियाबंद.

2. उपरोक्त नियुक्तियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :—

- (1) इन्हें दिव्यांगता संबंधी जिला मेडिकल बोर्ड से इस विभाग के ज्ञापन दिनांक 29-05-2023 की अपेक्षा अनुसार दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व पदस्थापना संबंधी संस्था द्वारा कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावेगा।

- (2) उपरोक्तानुसार 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नानुसार स्टापपेण्ड देय होगा :—  
 प्रथम वर्ष — पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत.  
 द्वितीय वर्ष — पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत.  
 तृतीय वर्ष — पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत.

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टापपेण्ड के साथ अन्य भत्ते शासकीय सेवक की तरह प्राप्त होंगे.

- (3) अभ्यर्थी को मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के योग्य पाये जाने की प्रत्याशा में नियुक्त किया जा रहा है. मेडिकल बोर्ड द्वारा शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाने की स्थिति में नियुक्ति आदेश निरस्त हो जायेगा. मेडिकल बोर्ड का स्वस्थता प्रमाण पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
- (4) शासकीय अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत होने की स्थिति में अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा.
- (5) कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. मूल प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति संचालनालय रोजगार एवं प्रशिक्षण में जमा करना होगा.
- (6) अभ्यर्थी को स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लायसेंस, पेन कार्ड, पासपोर्ट) मूल रूप से प्रस्तुत करेगा. जिसकी सत्यापित छायाप्रति संचालनालय, रोजगार एवं प्रशिक्षण के कार्यालय में रहेगी.
- (7) परिवीक्षा अवधि के दौरान किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएं समाप्त की जा सकेंगी.
- (8) अभ्यर्थी के परिवीक्षा अवधि, स्थायीकरण, वरिष्ठता आदि छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 एवं विभागीय सेवा भर्ती नियम के अंतर्गत शासित होगी.
- (9) नियुक्त अधिकारी को आदेश जारी होने के दिनांक से 15 दिवस के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त माना जावेगा. आदेश में टंकण त्रुटि होने पर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी ही मान्य की जावेगी.
- (10) अभ्यर्थी द्वारा दी गई जानकारी/प्रमाण पत्र यदि गलत पाये गये, तो उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के सेवा से पृथक् किया जा सकेगा तथा उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही की जा सकेगी.
- (11) चयनित प्रत्याशियों को पदस्थापना स्थान तक जाने हेतु किसी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा.
- (12) उपर्युक्त नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर एस.एल.पी. (सी) क्रमांक 19668/2022 में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अध्वधीन होगी.

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
**विजया खेस्र, उप सचिव.**

**वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग**  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 जुलाई 2023

क्रमांक एफ 1-01/2023/10-भा.व.से.—राज्य शासन एतद्वारा निम्नलिखित भारतीय वन सेवा अधिकारियों को प्रशासनिक दृष्टिकोण से उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए कॉलम क्रमांक-4 अनुसार नवीन पद पर अस्थाई रूप से, आगामी आदेश पर्यन्त पदस्थ करता है :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री व्ही. शेट्टेपनावर (1992)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी मिशन लाइफ, कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) एवं नोडल अधिकारी मिशन लाइफ, कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर.
2.	श्री अरूण कुमार पाण्डेय (1994)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव (छ.ग. राज्य जैव-विविधता बोर्ड) एवं संयुक्त वन प्रबंधन तथा नोडल अधिकारी, छ.ग. राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास/ योजना) एवं सदस्य सचिव (छ.ग. राज्य जैव-विविधता बोर्ड) तथा नोडल अधिकारी, छ.ग. राज्य जलवायु परिवर्तन प्रकोष्ठ.
3.	श्री ओ. पी. यादव (1995)	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) एवं अतिरिक्त प्रभार अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कैम्पा, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर (प्रतिनियुक्ति पर).
4.	श्री राजेश कुमार पाण्डेय (2001)	मुख्य वन संरक्षक इको-टूरिज्म (पारिस्थितिकी पर्यटन), अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर.	मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं परियोजना संचालक, इंद्रावती टायगर रिजर्व, जगदलपुर.
5.	श्री एस. पी. पैकरा (2002)	मुख्य वन संरक्षक (बांस मिशन) अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर.	प्रभारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण), अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर.
6.	श्री बी. पी. सिंह (2002)	मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग	मुख्य वन संरक्षक (सतर्कता/शिकायत) कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर.
7.	श्री एस. वेंकटाचलम (2005)	मुख्य वन संरक्षक एवं संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, कैम्पा, अरण्य भवन, नवा रायपुर, अटल नगर (प्रतिनियुक्ति पर).	मुख्य वन संरक्षक (बांस मिशन) अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर.
8.	श्री के. मैचियो (2006)	वन संरक्षक (सतर्कता/शिकायत) कार्या. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर.	प्रभारी मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) एवं क्षेत्रीय निदेशक, उदंती-सीतानदी टायगर रिजर्व, रायपुर.

(1)	(2)	(3)	(4)
9.	श्री दिलराज प्रभाकर (2008)	वन संरक्षक (विकास/योजना) अरण्य भवन, नवा रायपुर अटल नगर.	प्रभारी मुख्य वन संरक्षक, दुर्ग वृत्त, दुर्ग

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. के. चंचलानी, अवर सचिव.

### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,  
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

जशपुर, दिनांक 24 फरवरी 2023

क्रमांक/01/अ-82/2022-23.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

### अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	बालाछापर	2.140	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग जशपुर, उपसंभाग	बालाछापर, आरा, सकरडेगा मार्ग.
		शासकीय भूमि	1.856	क्रमांक 01.	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 24 फरवरी 2023

क्रमांक/03/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	सकरडेगा	2.526	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग जशपुर, उपसंभाग	बालाछापर, आरा, सकरडेगा मार्ग.
		शासकीय भूमि	2.048	क्रमांक 01.	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 24 फरवरी 2023

क्रमांक/04/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	बोकी+टुकूटोली	3.405	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग जशपुर, उपसंभाग	बालाछापर, आरा, सकरडेगा मार्ग.
		पट्टी 01 एवं 02			
		शासकीय भूमि	0.526	क्रमांक 01.	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 24 फरवरी 2023

क्रमांक/05/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	बोकी (बरटोली) शासकीय भूमि	2.597  0.758	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग जशपुर, उपसंभाग क्रमांक 01.	बालाछापर, आरा, सकरडेगा मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 24 फरवरी 2023

क्रमांक/06/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	आरा  शासकीय भूमि	3.827  1.737	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग जशपुर, उपसंभाग क्रमांक 01.	बालाछापर, आरा, सकरडेगा मार्ग.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.



जशपुर, दिनांक 24 फरवरी 2023

क्रमांक/09/अ-82/2022-23.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जायेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 12 के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जशपुर	जशपुर	ईचकेला	3.903	अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग जशपुर, उपसंभाग	बालाछापर, आरा, सकरडेगा मार्ग.
		शासकीय भूमि	0.363	क्रमांक 01.	

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जशपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रवि मित्तल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं  
पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं  
आपदा प्रबंधन विभाग

खसरा नम्बर  
(1)  
रकबा  
(हेक्टेयर में)  
(2)

जशपुर, दिनांक 14 जून 2023

रा.प्र.क्रमांक 202108032100030/01/अ-82/2020-21.—  
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

## अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-फरसाबहार

(ग) नगर/ग्राम-फरसाबहार

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.140 हेक्टेयर

योग

107	0.012
32/2	0.012
104/2	0.006
43	0.006
40/1	0.004
41/1	0.008
41/2	0.008
42/1	0.008
45	0.004
44/2	0.004
47/2	0.012
48	0.006
49	0.020
50/2	0.006
75	0.024

13	0.140
----	-------

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बंदरचुंवा से फरसाबहार सड़क निर्माण.		(1)	(2)
		107/3	0.010
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), फरसाबहार के कार्यालय में किया जा सकता है.		107/9	0.012
		102/1	0.009
		104/7	0.006
जशपुर, दिनांक 14 जून 2023		104/9	0.012
		115	0.003
रा.प्र.क्रमांक 202109032100005/04/अ-82/2020-21.—		102/2/7	0.006
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		102/2/6	0.006
		88	0.006
		120/2	0.018
		94/2/2	0.028
		121	0.006
		125	0.019
अनुसूची		335/1	0.008
		365/3	0.004
(1) भूमि का वर्णन—		365/1	0.004
(क) जिला-जशपुर		366	0.008
(ख) तहसील-फरसाबहार		368	0.010
(ग) नगर/ग्राम-बनगांव		306/1	0.012
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.654 हेक्टेयर		369	0.012
खसरा नम्बर		383	0.034
रकबा		289/1	0.026
(हेक्टेयर में)		288/2	0.012
(1)	(2)	288/1	0.018
29	0.044	279/2	0.016
28	0.024	282	0.030
35	0.022	415/1	0.014
33/3	0.046	376/2	0.002
33/2	0.024		
34	0.023		
37/2	0.028	योग	42 0.654
35/1	0.020		
35/2	0.012		
36	0.020		
107/4	0.010		
331	0.008		
107/2	0.010		
107/5	0.012		
		(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बंदरचुंवा से फरसाबहार सड़क निर्माण.	
		(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), फरसाबहार के कार्यालय में किया जा सकता है.	
		छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रवि मित्तल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.	

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-बिलासपुर, छत्तीसगढ़	(1)	(2)
एवं पदेन उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व		
एवं आपदा प्रबंधन विभाग	254/14	0.061
	255	0.384
बिलासपुर, दिनांक 3 जुलाई 2023	256/1	0.243
	291/4	0.486
क्रमांक 12/अ-82/2018-19.— चूंकि राज्य शासन को इस	268/2, 268/4	0.809
बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में	268/1	0.405
वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक	268/3	0.405
प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और	268/8	0.085
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार	268/5	0.202
अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा	268/10	0.061
जावेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता	268/11	0.061
है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		
अनुसूची		
(1) भूमि का वर्णन—	योग	
(क) जिला-बिलासपुर	13	3.769
(ख) तहसील-बोदरी		
(ग) नगर/ग्राम-मोहभट्टा		
(घ) लगभग क्षेत्रफल-3.769 हेक्टेयर		
खसरा नम्बर	रकबा	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-औद्योगिक
(1)	(2)	प्रयोजन (रेल्वे साईडिंग) निर्माण हेतु.
254/13	0.567	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी
		(राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में किया जा सकता है.
		छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
		सौरभ कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

## विभाग प्रमुखों के आदेश

### कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) जिला उत्तर बस्तर कांकेर

उत्तर बस्तर कांकेर, दिनांक 14 जुलाई 2023

क्रमांक 86.—छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 4-137/सात-1/2013 दिनांक 01-01-2014 के माध्यम से छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 90 सहपठित धारा 68 व 73 के अंतर्गत राजस्व ग्राम का गठन करने संबंधी बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियां अद्योहस्ताक्षरकर्ता में निहित किया गया है. जिसके तहत ग्राम पंचायत चांदीपुर प.ह.नं.-09 रा.नि.मं. पखांजूर तहसील पखांजूर में स्थित ग्राम चांदीपुर (पी.व्ही.-28) से आश्रितपारा पी.व्ही.-36 को पृथक कर नवीन राजस्व ग्राम नवीनपल्ली (पी.व्ही.-36) घोषित करने हेतु अभिलेखों का प्रारंभिक प्रकाशन अधिसूचना क्रमांक 1314 दिनांक 21-10-2022 को किया गया था. जिसमें किसी भी प्रकार की कोई दावा आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ.

अतः छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 68, 69, 70, 72 तथा 73 के अधीन दिये गये शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा घोषित किया जाता है कि नीचे अनुसूची के कॉलम (2) में दर्शित आश्रित ग्राम, इस अधिसूचना दिनांक से एक राजस्व ग्राम होगा, अर्थात् :-

स.क्र.	ग्राम का नाम	ग्राम का कुल रकबा	ग्राम की सीमाएं	पटवारी हल्का नंबर	ग्राम पंचायत का नाम	तहसील	जिला
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	नवीनपल्ली (पी.व्ही.-36)	277.78	उत्तर दिशा में — रक्षितवन एवं ग्राम कोयगांव दक्षिण दिशा में — चांदीपुर पी.व्ही.-28 एवं पी.व्ही. 29, 30, योगेन्द्र नगर पूर्व दिशा में — पी.व्ही. 114 भरतपुर पश्चिम दिशा में — हांकेर एवं रक्षित वन.	09	चांदीपुर	पखांजूर	उत्तर बस्तर कांकेर

No. 86.— Government of Chhattisgarh, Revenue Department vide notification number F 4-137/Seven-1/2013 dated 01-01-2014 under section 90 read with section 68 and 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) The powers of the settlement officers regarding formation of revenue village have been vested in the undersigned. Under which Gram Panchayat Chandipur P.C. No.-09 RI Circle Pakhanjur Initial publication of records notification number 1314 dated 21-10-2022 to declare new revenue village Naveenpalli (P.V.-36) by separating the relaint subvillage naveenpalli (P.V.-36) from village Chandipur (P.V.-28) in Pakhanjur tehsil was done. In which no claim objection of any kind was received.

Therefore, in exercise of the powers conferred under Section 68, 69, 70, 72 and 73 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959, it is hereby declared that the dependent villages shown in column (2) of the Schedule below, from the date of this notification shall be a revenue village, namely :—

S. No.	Name of forest Village	Total Area of Village (in hectare)	Boundaries of forest village	Patwari Halka Number	Name of Gram Panchayat	Tahsil	District
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Naveenpalli (P.V.-36)	277.78	<b>North—</b> Rakshitvan and village Koygaon <b>South—</b> Chandipur P.V.-28 and P.V. 29, 30, Yogendra Nagar. <b>East-</b> P.V. 114 Bharatpur <b>West—</b> Hanker and Protected forest.	09	Chandipur	Pakhanjur	Uttar Bastar Kanker

डॉ. प्रियंका शुक्ला,  
कलेक्टर.

## संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर (छ.ग.)

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 11 अगस्त 2023

क्रमांक 37/उपांतरण-8/नग्रा.नि./2023.—संचालक एतद्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अंतर्गत संचालनालय की सूचना क्रमांक 2341/उपांतरण-8/नग्रा.नि./2022, दिनांक 05-09-2022 द्वारा रायगढ़ विकास योजना 2021 में व्यक्तिगत प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुए दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में एक दिन प्रकाशित की गई थी :—

## रायगढ़ विकास योजना 2021 में उपांतरण

क्र.	ग्राम का नाम/ प.ह.नं.	खसरा क्रमांक	रकबा	अंगीकृत विकास योजना में दर्शित भू-उपयोग	छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 23-क (1) के खण्ड (ख) के तहत उपांतरण हेतु प्रस्तावित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	भगवानपुर तहसील-रायगढ़ प.ह.नं.-00024	127/13, 127/16, 127/19, 132/4, 132/5, 132/10, 132/17, 127/2, 132/106, 132/107, 132/108, 132/109, 132/110, 132/111, 132/112, 132/117, 132/118, 132/119 & 132/121	1.913 हेक्ट.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	व्यावसायिक
2.		127/15	0.054 में से 0.040 हेक्ट.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	व्यावसायिक (0.014 हेक्ट. मार्ग छोड़कर)
3.		127/18	0.166 में से 0.153 हेक्ट.	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	व्यावसायिक (0.013 हेक्ट. मार्ग छोड़कर)

## कुल रकबा

2.106 हेक्ट.

- उक्त उपांतरण श्री राजेश जिंदल, डायरेक्टर, रियलस्टीक, बिल्डकॉन प्रा.लि. द्वारा रायगढ़ विकास योजना 2021 के ग्राम-भगवानपुर, प.ह.नं.-00024, तहसील व जिला-रायगढ़ स्थित भूमि कुल रकबा 2.1330 हेक्ट. भूमि प्रस्तावित मार्ग अंतर्गत प्रभावित भूमि (0.027 हेक्ट.) छोड़कर शेष भूमि 2.106 हेक्ट. का विकास योजना में दर्शित भूमि उपयोग सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु है.
- सूचना में उल्लेखित निश्चित समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.
- राज्य शासन द्वारा रायगढ़ विकास योजना 2021 में उपरोक्त उपांतरण का अनुमोदन किया गया है. उक्त उपांतरण रायगढ़ विकास योजना 2021 का अंगीकृत भाग होगा.

जे. पी. पाठक,  
आयुक्त.

**उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं****HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR**

Bilaspur, the 21st July 2023

No. 38/L.G./2023/II-2-11/2008.—Shri Anand Kumar Dhruw, District & Sessions Judge, Koriya (Baikunthpur) is hereby, granted earned leave for 04 days from 10-06-2023 to 13-06-2023 in continuation of summer vacation along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Dhruw, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 288 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 21st July 2023

No. 39/L.G./2023/II-3-2/2009.—Shri Jaideep Vijay Nimonkar, the then District & Sessions Judge, Bemetara is hereby, granted earned leave for 05 days from 06-05-2023 to 10-05-2023 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 05-05-2023 till before the Court hours of 11-05-2023 and earned leave for 12 days from 05-06-2023 to 16-06-2023 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Nimonkar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 214 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 21st July 2023

No. 40/L.G./2023/II-3-7/2015.—Shri Santosh Sharma, District & Sessions Judge, Raipur is hereby, granted earned leave for 07 days from 10-06-2023 to 16-06-2023 in continuation of summer vacation along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Sharma, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 211 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 21st July 2023

No. 41/L.G./2023/II-2-24/2016.—Shri Alok Kumar, Judge, Family Court, Kabirdham (Kawardha) is hereby, granted earned leave for 06 days from 19-06-2023 to 24-06-2023 along with permission to remain out of headquarters from 17-06-2023 to 25-06-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kumar, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+14 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 21st July 2023

No. 42/L.G./2023/II-3-32/2007.—Shri D. N. Bhagat, Special Judge (Atrocities), Surguja (Ambikapur) is hereby, granted earned leave for 05 days from 01-06-2023 to 05-06-2023 along with permission to remain out of headquarters from 01-06-2023 to 05-06-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Bhagat, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 21st July 2023

No. 43/L.G./2023/II-2-10/2007.—Shri K. Vinod Kujur, Registrar (Judicial), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 05 days from 05-06-2023 to 09-06-2023 with summer vacation along with permission to leave headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Kujur, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 21st July 2023

No. 44/L.G./2023/II-2-12/2008.—Shri Bhuneshwar Ram, Judge, Family Court, Korba is hereby, granted earned leave for 07 days from 02-05-2023 to 08-05-2023 along with permission to remain out of headquarters.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Ram, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 21st July 2023

No. 45/L.G./2023/II-2-5/2016.—Shri Hirendra Singh Tekam, Special Judge (Atrocities), Raipur is hereby, granted earned leave for 07 days from 08-05-2023 to 14-05-2023 with summer vacation along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 06-05-2023 till before the Court hours of 25-05-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tekam, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 21st July 2023

No. 46/L.G./2023/II-2-6/2022.—Shri Vivek Kumar Tiwari, Additional Principal Judge, Family Court, Janjgir-Champa is hereby, granted earned leave for 04 days from 10-04-2023 to 13-04-2023 along with permission to remain out of headquarters from 07-04-2023 to 16-04-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Tiwari, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

Bilaspur, the 21st July 2023

No. 47/L.G./2023/II-3-35/2007.—Shri Ramashankar Prasad, Principal Judge, Family Court, Bilaspur is hereby, granted earned leave for 04 days from 10-04-2023 to 13-04-2023 along with permission to remain out of headquarters from 07-04-2023 to 16-04-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Prasad, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 300+15 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.



Bilaspur, the 21st July 2023

No. 48/L.G./2023/II-3-26/2014.—Shri Sirajuddin Qureshi, the then District & Sessions Judge, Balrampur at Ramanujanj is hereby, granted earned leave for 06 days from 24-04-2023 to 29-04-2023 along with permission to remain out of headquarters after the Court hours of 21-04-2023 till 30-04-2023.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Qureshi, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 230 days of earned leave are remaining in his leave account as on date.

By order of the High Court,  
AWADH KISHORE, Additional Registrar (ADMN.)

बिलासपुर, दिनांक 5 जुलाई 2023

क्रमांक 368/दो-3-20/2011.—श्री भीष्म प्रसाद पाण्डेय, तत्कालीन जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जशपुर, वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुंद (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 18-05-2023 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 19 जुलाई 2023

क्रमांक 381/दो-2-11/2017.—डॉ. प्रज्ञा पचौरी, तत्कालीन न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, राजनांदगांव, वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बालोद (छ.ग.) को उनके आवेदन पत्र दिनांक 23-06-2023 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात् दिनांक 01-11-2017 से 31-10-2019 हेतु उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ.ग./06 दिनांक 31-10-2006 के आलोक में प्रदान की जाती है.

आदेशानुसार,

आर. पी. देवांगन,  
बजट अधिकारी.